

# India to stop import of thermal coal from Financial Year 2023-24 - Pralhad Joshi

Posted On: 18 FEB 2020 5:42PM by PIB Delhi

India will stop importing thermal coal from Financial Year 2023-24, said Union Minister of Coal and Mines Shri Pralhad Joshi while chairing “Chintan Shivir” - a two day brainstorming session. The session was organized to find a way forward for the coal sector - at Kevadia in Gujarat on 17th and 18th February 2020.

“The Shivir has engaged the participants in contemplating and deliberating to think out of the box to overcome various bottlenecks and provide innovative solutions to the Indian coal sector” Shri Pralhad Joshi said while interacting with the media on the sidelines of the Shivir.



Highlighting key takeaways of the Shivir, Union Coal and Mines Minister said that various ways and means were discussed with key stakeholders to achieve 1 billion tonnes (BT) coal production target by Coal India Limited (CIL) by Financial Year 2023-24. The Ministry of Coal will coordinate with Indian Railways and Shipping Ministry and enable CIL, Captive and Commercial Miners evacuate more coal by 2030.

Stressing upon the diversification in the Indian Coal sector, the Minister said that ideas have also been mooted that CIL could think of coming up with the state of the art pithead thermal power plants to transform it into an integrated energy company. It was also proposed that CIL could generate 5 GW of solar power by FY 2023-24 and could diversify into coal gasification with a target of 50 Million Tonnes by 2030 enabling a sustainable energy mix for the country. All these ideas will be deliberated, studied and examined for their feasibility in detail and based on that, they could be implemented.

The Minister further stressed upon the safety of workers in the Coal mining sector and has urged coal companies to achieve zero mortality rate by FY 2023-24.

He also announced that the Ministry of Coal will introduce a “Coal Minister's Award” soon to recognize and appreciate best practices in coal production, productivity, safety, sustainability etc. by the coal companies.

The Minister further stated that drilling agencies like Central Mine Planning and Design Institute(CMPDI) and Geological Survey of India (GSI) should benchmark their operations to global

standards by digitizing their databases. He added that it will enable better utilization in years to come.

During the two day Shivar, strategies were evolved for sustainable mining, environmental conservation, use of clean coal technologies and for extending helping hand to all stakeholders in and around coal mining areas to coexist in a mutually sustainable manner.

\*\*\*\*\*

**RJ/NG/RM**

(Release ID: 1603554)

# भारत वित्त वर्ष 2023-24 से थर्मल कोल का आयात रोकेगा : प्रह्लाद जोशी

प्रविष्टि तिथि: 18 FEB 2020 5:42PM by PIB Delhi

केन्द्रीय कोयला तथा खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 से थर्मल कोल (ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग आने वाला कोयला) का आयात करना रोक देगा। श्री जोशी गुजरात के केवडिया में 17 और 18 फरवरी, 2020 को कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों के बारे में आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे।

शिविर से अलग मीडिया से बातचीत करते हुए श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शिविर में भाग लेने वाले प्रतिनिधि भारतीय कोयला क्षेत्र की विभिन्न बाधाओं को दूर करने तथा नवाचारी समाधान प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं।



श्री जोशी ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के एक बिलियन टन उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। सीआईएल, कैप्टिव और वाणिज्यिक खनिकों को 2030 तक अधिक कोयला निकालने में सक्षम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय, भारतीय रेल तथा जहाजरानी मंत्रालय के साथ तालमेल करेगा।

भारतीय कोयला क्षेत्र में विविधता पर बल देते हुए श्री जोशी ने कहा कि यह विचार सामने आया है कि सीआईएल अपने आधुनिक खदान निकासी ताप विद्युत संयंत्रों को एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में परिवर्तित करे। यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि सीआईएल वित्त वर्ष 2023-24 तक 5 गीगावॉट सौर विद्युत का उत्पादन कर सकती है और 2030 तक 50 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करके अपना विस्तार कर सकती है। इससे देश सतत ऊर्जा मिश्रण में सक्षम होगा। इन सभी विचारों पर अध्ययन किया जाएगा और विस्तार से संभावना की जांच की जाएगी और इसी के आधार पर उन्हें लागू किया जाएगा।

कोयला खनन क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा की चर्चा करते हुए कोयला और खान मंत्री ने कोयला कंपनियों से आग्रह किया कि वे वित्त वर्ष 2023-24 तक शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करें।

उन्होंने घोषणा की कि कोयला मंत्रालय कोयला उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, स्थायित्व में कोयला कंपनियों श्रेष्ठ व्यवहारों को मान्यता देने के लिए कोयला मंत्री का पुरस्कार प्रारंभ करेगा।

उन्होंने कहा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) जैसी ड्रिलिंग एजेंसियों को डाटा बेस का डिजिटिकरण करके अपने संचालनों को ग्लोबल मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में बेहतर उपयोग होगा।

दो दिन के शिविर में स्थायी खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी उपयोग तथा कोयला खनन क्षेत्र में लगे सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए रणनीतियां विकसित की गईं।

**एस.शुक्ला/एएम/एजी/जीआरएस-5819**

(रिलीज़ आईडी: 1603574) आगंतुक पटल : 94

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Urdu , English , Gujarati